Product	*Country*	*Initiation Date*	*Date of Find Findings*
11. LCFC	Russia, Kazakhstan	6.6.95	3.12.96
12. 8-Hydroxy quinoline	China	4.3.96	6.9.96@
13. Bisphenol-A	U S A	20.11.95	25.10.96@
14. Nitrile Rubber	Germany, South Korea	15.3.95	Under Examination
15. Catalyspts	Denmark	6.9.96	-do-
16. Acrylic Fibre	USA, Thailand, Korea RP	13.9.96	-do-
17. Graphite Electrodes	USA, China, Germany, Itlay Belgium, Austria, France, Spain	30.9.96	-do-

@Date of Preliminary Findings

Statement B

Country	Products Involved
USA	Steel Pipes and Tubes, Sulfanilic Acid, SS Wire Rod, SS flanges, SS Bars, Iron Metal Castings.
Canada	Carbon Steel Welded Pipes, Granite
E.E.C.	Polyester Blended Yarns, Oxalic Acid, Polyester Staple Fibre, Unbleached Cotton Fabrics*, Synthetic Fibre Ropes*, Bed Linen*, SS Fasteners*
China & Japan	Nil

*No definitive duties imposed so far

श्रमिकों के घायल होने या अपंग होने की घटनाओं में वृद्धि

2448. **श्री राम जेठमलानी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप श्रमिकों के घायल होने, मृत्यु होने या अपंग होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1,000 श्रमिकों में से 4 श्रमिक प्रत्येक वर्ष उद्योगों में अपनी ड्यूटी पर रहते हुए ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(घ) क्या विभिन्न उपायों द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को रोका या घटाया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए किन-किन उपायों की पहचान की गयी है और उसे कार्यान्वित करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ग) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, श्रमिकों के घायल होने, मृत्यु होने या अपंग होने की घटनाएं घटती-बढ़ती रहती हैं और इनकी

कोई निश्चित प्रवणता नहीं होती है। कारखानों में नियोजित प्रत्येक 1000 कर्मकार के घायल होने की दर चार से अधिक है।

(घ) और (ङ) कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। कारखानों के मालिक कारखाना अधिनियम के उपबंधों, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। कारखाना अधिनियम के उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्टतः खतरनाक प्रक्रियाओं में सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं को सुदृढ़ करने और उल्लंघन की दशा में दण्डात्मक प्रावधानों की व्यवस्था करने की दृष्टि से वर्ष 1987 में संशोधन किया गया था। सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर्मकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने की मालिकों को विशिष्ट जिम्मेदारी दी गई है। कर्मकारों को ये अधिकार दिए गए हैं कि मालिक को सम्भावित खतरे के बारे में सावधान करें। कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई, जोकि श्रम मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को तकनीक और अन्य मार्ग दर्शन प्रदान करने के अलावा, कारखाना निरीक्षकों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है और अध्ययन और सर्वेक्षण भी करता है।

Wagon manufacturing capacity in the country

2449. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is surplus Wagon manufacturing capacity in the country as reported in the Indian Express dated 16th September, 1996;

(b) whether fresh capacity is being created without adequate justification; and

(c) if so, the total cost involved therein?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) It has been brought to the notice of the Government by the wagon building manufacturers in the past that their capacity is under utilised due to lack of sufficient orders from the Railways. However, the requirments of wagons depend on transport needs and very from year to year.

(b) and (c) Wagon manufacturing is a delicensed industry. Entrepreneurs desirous of setting up wagon manufacturing units are only required to file Industrial Entrepreneurs Memorandum (IEM) with the Secretariat for Industrial Assistance. No decision has so far been taken to create fresh wagon capacity in the Railways.

Reimbursement of Central investment subsidy

2450. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether any amount is due to Kerala by way of reimbursement of Centreal investment subsidy;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reasons for delay in making the payments; and

(d) whether Government will take steps to pay the amount to the State Government immediately?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) The Central Investment Subsidy Scheme which was introduced in August, 1971 for promoting industrialisation of backward areas, ceased to exist on 30th September, 1988. On Cessation of the Scheme, certain industries went in appeal to various High Courts/Supreme Court in the matter. The Supreme Court vide its judgement dated the 5th December, 1995, directed that all application, which were filed before 30th September 1988 may be considered for grant of Central Investment Subsidy, provided the applications were found complete under the Scheme Consequently, all the States/Union Territories as also the State of Kerala have been directed to comply with the Supreme Court Judgement and ensure